

an>

Title: Need to reserve various posts in PSUs of Gujarat for recruitment of local people.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : केन्द्र और राज्य सरकारों की नीति श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की होती है। गुजरात राज्य की वर्तमान रोजगार नीति के अनुसार राज्य में प्रस्थापित राज्य एवं केन्द्र सरकार के औद्योगिक ईकाईयों तथा निजी प्रोत्साहित औद्योगिक ईकाईयों में तमाम पदों में से मिनिमम 85 प्रतिशत पदों तथा मैनेजर, सुपरवाइजर के पदों पर मिनिमम 60 प्रतिशत जगहें गुजरात राज्य में 15 सालों से स्थायी तौर पर रहते हुए स्थानिक व्यक्तियों से भरी जाती है।

मेरी मांग है कि इस गुजरात मॉडल के आधार पर केन्द्र सरकार के सभी औद्योगिक इंटरप्राइजिस तथा ज्वाइंट क्षेत्रीय उद्योग घरानों में कर्मचारी, कामगार, कारीगर वर्ग की मिनिमम 85 प्रतिशत भर्ती तथा मैनेजीरियल और सुपरवाइजरी जगहों पर मिनिमम 60 प्रतिशत भर्ती स्थानिक लोगों की ही करनी चाहिए क्योंकि स्थानिक राज्य सरकार द्वारा भूमि, पानी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी जाती है।

आधुनिक लोकतंत्र कल्याणकारी लोकतंत्र कहलाता है। इसमें श्रमिकों का योगदान देश के उत्थान में मील का पत्थर होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी श्रमेव जयते का नारा है उसको यर्थाथ रूप देने हेतु स्थानिक श्रमिकों को एक प्रकार का भर्ती का आरक्षण दिया जाए इसके लिए नियम न हों तो नियम बनाए जाएं तथा उनको क्रियान्वयन में लाया जाना चाहिए।